सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 262 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, रविवार 05 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

बंगाल की खाड़ी का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बरसात

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर संभाग के कई जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में भी शनिवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। बीते 12 घंटे में शहर में करीब 15 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश बढ़ने से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के पास बने सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र तथा सक्रिय मानसूनी द्रोणिका के कारण प्रदेश में अच्छी बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। इससे आने वाले दिनों में अधिकांश जिलों में वर्षा की गतिविधियां तेज बनी रह सकती हैं।

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सख्त

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट (सीएसईएएम) को लेकर मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है, जो सीएसईएएम को बढ़ावा देते हैं या ऐसे कंटेंट तक पहुंच आसान बनाते हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मेटा से सात दिनों के भीतर इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय मेटा की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली, विज्ञापनों की समीक्षा प्रक्रिया और उसके प्लेटफॉर्म पर अवैध एवं हानिकारक सामग्री के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांग सकता है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले पर मेटा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

पद्मविभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम साय बोले- अपूरणीय क्षति

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति व पंडवानी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। उन्होंने 70 साल उम्र में रविवार तड़के 3:15 बजे रायपुर एम्स अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ थीं और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम साय ने तीजन बाई के निधन को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था।

बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। महिलाओं के लिए उस दौर में पंडवानी की 'कापालिक शैली' में प्रस्तुति देना वर्जित माना जाता था, लेकिन तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई।

13 साल की उम्र में दी पहली प्रस्तुति

तीजन बाई ने 13 साल की उम्र में सबसे चंद्रखुरी में अपनी प्रस्तुति दी। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। तीजन बाई ने भारत के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत अनेक देशों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ की लोककला का डंका बजाया। उनकी कला की सराहना देश-विदेश में हुई। तीजन बाई को कला क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं- पद्मश्री (1988) संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1995) पद्मभूषण (2003), पद्म विभूषण (2019) शामिल हैं।

डॉ. तीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर पहुंचकर पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला-साधना और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने पंडवानी को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई तथा छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। डॉ. तीजन बाई का निधन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है।

पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!

चिंतन शिविर 3.0: सीएम साय ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ की। भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशेष योग सत्र में उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि

नियमित योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन और प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से चिंतन शिविर के दौरान दिन की शुरुआत योग से की गई, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श किया जा सके। योग सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

कोरबा में गैस सिलेंडर फटा, बाल-बाल बचे मां-बेटे, घर की दीवारें क्षतिग्रस्त

कोरबा। शहर के मानिकपुर चौकी क्षेत्र की रामनगर बस्ती में शनिवार देर रात गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में मकान मालिक गजानंद साहू की पत्नी और दो बच्चे बाल-बाल बच गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, गजानंद साहू के घर की रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लीकेज हो गया, जिससे अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और छत के परखच्चे उड़ गए।

धमाके के बाद घर में रखे फ्रिज और एक दूसरे गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। कुछ ही सेकंड में फ्रिज भी फट गया, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास की बस्ती के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।

पहली तेज बारिश में ही टपकने लगा रायपुर रेलवे स्टेशनःप्लेटफॉर्म पर झरना बना शेड

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ए-1 श्रेणी में शामिल रायपुर रेलवे स्टेशन शनिवार को मानसून की पहली तेज बारिश में ही बदहाल नजर आया। शाम करीब 5 बजे हुई जोरदार बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर-1 के शेड से पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा।

छत के नीचे खड़े यात्री भी भीगने लगे, जिससे प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई।बारिश से बचने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अपना सामान उठाकर सूखी जगह की तलाश में इधर-उधर भागते रहे। प्लेटफॉर्म पर पानी भरने और लगातार टपकते पानी की वजह से लोगों को चलने में भी परेशानी हुई। हैरानी की

बात यह रही कि कुछ देर की बारिश में ही स्टेशन की यह स्थिति सामने आ गई। स्टेशन पर मौजूद कई यात्रियों ने शेड से गिरते पानी और अव्यवस्था का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

बंगाल में अदाणी समूह बनाएगा 2000 बेड का अस्पताल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, अदाणी समूह न्यू टाउन में 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल स्थापित करेगा। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें आधे यानी 1000 बेड गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रहेंगे।

सरकार का कहना है कि इससे राज्य के लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान इस परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदाणी समूह ने सरकार को लिखित रूप से 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाने की प्रतिबद्धता दी है। उनके अनुसार, अस्पताल के 1000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुफ्त इलाज के लिए रखे जाएंगे, जबकि बाकी 1000 बेड व्यावसायिक संचालन के तहत इस्तेमाल होंगे।

मजदूरों से भरी पिकअप पलटी और पेड़ से टकराई, हादसे में 9 घायल

कोरबा। जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह मजदूरों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और पेड़ से जा टकराई। दरगा गांव के मजदूर गोढ़ी स्थित कार्बन फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। बनखेता गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक का नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन सड़क किनारे पलटकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में 9 मजदूर घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाहन में 12 से अधिक मजदूर सवार थे। सूचना मिलने पर रजगामार चौकी पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट पहुंचे पीएम मोदी कर्मचारियों से किया संवाद, जाने अनुभव

साणंद। गुजरात के साणंद में भारत के तकनीकी भविष्य ने एक ऐतिहासिक उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सीजी सेमी के अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम का अंदाज बिल्कुल अलग दिखा। उन्होंने प्लांट के अंदर जाकर वहां काम करने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों से सीधे संवाद किया। उनकी पीठ थपथपाई और उनका हौसला बढ़ाया।

प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं से कहा कि आपका आत्मविश्वास ही भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाएगा। वहां मौजूद हर कर्मचारी

की आंखों में एक अलग चमक थी। वे समझ रहे थे कि वे सिर्फ चिप नहीं बना रहे, बल्कि भारत को एक नई तकनीकी महाशक्ति बनाने की नींव रख रहे हैं। कर्मचारियों ने भी पीएम के साथ अपना अनुभव साझा किया।

यह प्लांट कोई सामान्य फैक्ट्री नहीं है। इसके निर्माण में करीब 7,600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यह भारत का तीसरा ऐसा सेमीकंडक्टर प्लांट है, जहां कमर्शियल स्तर पर चिप पैकेजिंग का काम शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत के साथ-साथ जापान और थाईलैंड की तकनीकी साझेदारी भी शामिल है।

यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, रास्ता बंद

देहरादून। रविवार तड़के पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी से आगे अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। इधर, स्याना चट्टी के पास भी भूस्खलन के चलते कुछ समय के लिए यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बाधित रहा। हालांकि, एनएच की ओर से मलबा हटाने के बाद इस स्थान पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई। राज्य में भूस्खलन समेत अन्य कारणों के चलते 34 मार्ग बंद हैं। सबसे अधिक मार्ग पिथौरागढ़ जिले बंद रहे। इस सीमांत जिले में दस ग्रामीण मार्ग बंद है। देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में छह-छह, रुद्रप्रयाग दो, चमोली चार मार्ग बंद रहे। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संपादकीय

जानलेवा मैनहोल

सुरक्षित सड़कों की जवाबदेही तय हो

मानसून की बारिश जहां किसानों के लिये राहत लेकर आती हैं, वहीं तंत्र की काहिली और भ्रष्टाचार की पोल भी खोल देती है। मानसून की शुरुआती बारिश ने एक बार फिर सार्वजनिक संरचनाओं की जानलेवा खामियों को ही उजागर किया। मुंबई में बारिश के पानी में नजर न आने वाले एक खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हाल ही में खुले बहुचर्चित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली उजागर कर दी। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि बारिश के मौसम में स्थानीय निकायों की लापरवाही व खराब इंजीनियरिंग के चलते कैसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है। निस्संदेह, मुंबई में हुए हादसे को रोका जा सकता था। कथित साफ-सफाई के बाद लापरवाही से खुला छोड़ा गया मैनहोल तब जानलेवा बन गया, जब बारिश के पानी से ढका खुला मैनहोल नजर नहीं आया। निस्संदेह, दुर्घटना के बाद अधिकारियों को निलंबित करना और ठेकेदार को काली सूची में डालना, फौरी तौर पर सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि हादसे होने के बाद ही ऐसे कदम क्यों उठाये जाते हैं? पहले से ही नागरिकों की सुरक्षा के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं होती? कायदे से किसी सड़क पर मैनहोल खोलने से पहले बैरिकेड्स लगाने, चेतावनी देने वाले संकेत और अस्थायी कवर से ढकना बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं। जिन्हें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीते साल भी दिल्ली में भारी बारिश के दौरान स्कूटर फिसलने से एक महिला और उसका तीन साल का बेटा पानी से भरे नाले में बह गये थे। ये असुरक्षित ड्रेनेज संरचना की घातकता को ही दर्शाता है। विडंबना है कि हमारा तंत्र सालभर सोया रहता है और जब बरसात शुरू होने को होती है, तब मरम्मत- नालों की सफाई के काम की औपचारिकता पूरी करता है। निस्संदेह, संबंधित विभागों के अधिकारियों की सर्वकालिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। फिर किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निस्संदेह, मुंबई में हुए हादसे को रोका जा सकता था। कथित साफ-सफाई के बाद लापरवाही से खुला छोड़ा गया मैनहोल तब जानलेवा बन गया, जब बारिश के पानी से ढका खुला मैनहोल नजर नहीं आया। निस्संदेह, दुर्घटना के बाद अधिकारियों को निलंबित करना और ठेकेदार को काली सूची में डालना, फौरी तौर पर सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि हादसे होने के बाद ही ऐसे कदम क्यों उठाये जाते हैं? पहले से ही नागरिकों की सुरक्षा के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं होती? कायदे से किसी सड़क पर मैनहोल खोलने से पहले बैरिकेड्स लगाने, चेतावनी देने वाले संकेत और अस्थायी कवर से ढकना बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं। जिन्हें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीते साल भी दिल्ली में भारी बारिश के दौरान स्कूटर फिसलने से एक महिला और उसका तीन साल का बेटा पानी से भरे नाले में बह गये थे।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के धंसने की घटना भी एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई सड़क बारिश आने के कारण रातों-रात नहीं धंसती है। इसमें सड़क निर्माण के दौरान सतर्कता की अनदेखी भी शामिल है। दरअसल, सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की कारगर व्यवस्था न होने, मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित न करने और निर्माण में गुणवत्ता की कमी से ही बरसाती पानी सड़क की सतह के नीचे मिट्टी को धीरे-धीरे काटने लगता है। कालांतर यह मिट्टी का कटाव ही सड़क धंसने की वजह बन जाता है। साल 2024 में बिहार में पुलों के ढहने की शृंखला ने भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की हकीकत बतायी थी। इसी तरह की चिंताएं अकसर सामने आती हैं जब आधुनिक कहे जाने वाले महानगरों बेंगलुरू और मुंबई में हर मानसून में सड़कों में बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं इससे यातायात में भी अराजकता व व्यवधान पैदा होता है। बहरहाल, इन सभी घटनाओं के मूल में एक बात तो समान है कि स्थानीय निकाय व प्रशासन जोखिमों का समय रहते अनुमान नहीं लगा पाते हैं। यह तथ्य सभी अधिकारी जानते हैं कि एक निश्चित समय पर मानसून आता है। बाकायदा समय-समय पर सूचना माध्यमों में मौसम विभाग द्वारा मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन अधिकारी तब जागते हैं जब स्थितियां जटिल हो जाती हैं। वे इन हालातों को अप्रत्याशित आपात स्थिति के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। दरअसल,कई स्तरों पर होने वाली कमीशनखोरी व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अकसर ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं की जाती है। विडंबना यह भी है कि निरीक्षण भी अक्सर खानापूर्ति जैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक संरचना का रखरखाव भी निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक ही रहता है। वास्तव में कारगर समाधान के लिये जरूरी है कि मानसून से पहले सुरक्षा उपायों को संस्थागत ढंग से सुनिश्चित किया जाए, इंजीनियरिंग मानकों को सख्ती से लागू किया जाए, गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच हो और ठेकेदार को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाए। दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सुनिश्चित हो कि ऐसी घटनाएं हो ही न पाएं।

ई-जागृतिः डिजिटल भारत में उपभोक्ता न्याय के लिए नई परिकल्पना

प्रल्हाद जोशी

न्याय में देरी, लंबे समय से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी निराशाओं में से एक रही है। चाहे वह खराब उत्पाद हो, ऑनलाइन खरीदी गई वस्तु का न मिल पाना हो, या अनुचित सेवा अनुबंध हो, शिकायत दर्ज करने से लेकर राहत पाने तक की प्रक्रिया अक्सर धीमी, बोझिल और डराने वाली रही है। हालांकि, भारत की उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था समय के साथ लगातार विकसित हुई है, लेकिन इसे समर्थन देने वाली प्रणाली तेज़ी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के साथ कदम मिलाते हुए आगे नहीं बढ़ पायी।

आज, उपभोक्ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन बाज़ार में बड़े पैमाने पर लेन-देन करते हैं। उपभोक्ता न्याय की पारंपरिक व्यवस्था—जो भौतिक रूप से दाखिल करने, व्यक्ति द्वारा एक-एक कर जांच करने, अलग-अलग सॉफ़्टवेयर प्लेटफार्म का उपुओग करने और आमने-सामने की सुनवाई के इर्द-गिर्द बनायी गयी थी धीरे-धीरे अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केवल कानूनी सुधार ही पर्याप्त नहीं थे; इसके लिए न्याय देने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत थी।

यहीं पर ई-जागृति एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। यह सिर्फ एक तकनीक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के केंद्र में पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता को रखकर उपभोक्ता विवाद समाधान के तरीके की नए सिरे से परिकल्पना करने का प्रयास है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में एक आधुनिक फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गयी थी, जो बाज़ार की उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप काम करने में सक्षम हो। हालाँकि, कानून की भावना को प्रभावी सार्वजनिक सेवा में बदलने के लिए कई अलग-अलग पुरानी प्रणालियों को हटाकर एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाने की जरूरत थी। पुराने प्लेटफॉर्म में एकरूपता की कमी, पुरानी संरचना, एक-दूसरे से जुड़कर काम करने की सीमित सुविधा और भौतिक प्रक्रियाओं पर अधिक निर्भरता जैसी समस्याएँ थीं। कई उपभोक्ताओं के लिए—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अनिवासी भारतीय न्याय पाने की प्रक्रिया की लागत अक्सर एक बड़ी बाधा बन जाती थी।

ई- जागृति उपभोक्ता शिकायत की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करती है। ओटीपी आधारित पंजीकरण और ऑनलाइन दाखिल करने से लेकर डिजिटल जाँच, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, वर्चुअल सुनवाई, बहुभाषी आदेश और वास्तविक समय में मामले की निगरानी तक, यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को किसी भौगोलिक या प्रक्रियात्मक जटिलता की बाधा के बिना न्याय पाने में मदद करता है।

ऐसे बदलाव का महत्व केवल सुविधा तक ही सीमित नहीं है। यह नागरिकों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच रिश्ते को मौलिक रूप से बदल देता है। डिजिटल वर्कफ्लो कागजी काम को कम करते हैं, अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक जैसा बनाते हैं, विवेकाधीन देरी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। मामलों की स्वचालित सूची, ऑनलाइन डैशबोर्ड और तुरंत सूचना सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता को हर जानकारी मिलती रहे, जिससे प्रणाली में जनता का भरोसा मजबूत होता है।

इस प्लेटफॉर्म ने न्याय को और अधिक समावेशी बनाने के लिए उभरती तकनीकों को भी अपनाया है। एआई-सहायता प्राप्त मामला विश्लेषण, वॉइस-टू-टेक्स्ट कार्यप्रणाली, टेक्स्ट-टू-स्पीच सुविधा, बहुभाषी इंटरफेस, उन्नत सर्च क्षमता और पहुँच प्राप्त करने के उपकरण जैसी विशेषताओं के जरिए समाज के विभिन्न हिस्सों से अधिक लोगों की भागीदारी संभव हुई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोगों में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का देश भर में लागू होना भी उतना ही अहम रहा है,

जिससे वर्चुअल सुनवाई उपभोक्ता न्याय दिलाने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है। दूरदराज के जिलों या विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए, इससे कानूनी लड़ाई की वित्तीय और लॉजिस्टिक लागत दोनों काफी हद तक कम हो गई हैं।

फिर भी, इस स्तर के तकनीकी बदलाव में चुनौतियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं। डिजिटल सुधार अक्सर संस्थानों को स्थापित प्रथाओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करते हैं और उपयोगकर्ताओं को अपरिचित प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ई-जागृति की शुरुआत के दौरान, डेटा स्थानान्तरण, भुगतान गेटवे एकीकरण, इंटरफेस की उपयोगिता और लंबे समय से चल रहे मैनुअल प्रक्रियाओं में बदलाव को लेकर चिंताएँ उभरीं। कानूनी पेशेवरों और अन्य हितधारकों के कुछ हिस्सों ने नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाते समय कुछ चिंताएं जाहिर कीं।

इन चिंताओं को बाधा मानने की बजाय, कार्यान्वयन प्रक्रिया ने उन्हें निरंतर सुधार के मौकों के तौर पर देखा। उपभोक्ता आयोगों, कानूनी पेशेवरों, तकनीकी विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श से इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में मदद मिली। नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यशालाएं, वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र, साप्ताहिक शिकायत निवारण संवाद और लगातार तकनीकी समर्थन से हितधारकों का नई प्रणाली में धीरे-धीरे भरोसा बढ़ा। इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक मिला: डिजिटल परिवर्तन केवल इसलिए सफल नहीं होता कि तकनीक लागू की गई है, बल्कि इसलिए सफल होता है, क्योंकि संस्थाएं उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील रहती हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं।

शुरुआती परिणाम उत्साहवर्धक हैं। थोड़े ही समय में, ई-जागृति ने लाखों उपभोक्ताओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, दो लाख से अधिक मामलों के दाखिले की सुविधा दी है, उच्च समाधान दर हासिल की है और साठ से अधिक देशों के उपभोक्ताओं को भारत के उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। मानकीकृत डिजिटल वर्कफ्लो ने दक्षता में सुधार किया है और उन प्रक्रियात्मक अड़चनों को कम किया है, जो पहले की प्रणाली की विशेषता थी।

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार के माध्यम से मान्यता, न केवल एक संस्थागत उपलब्धि के रूप में, बल्कि सरकारी प्रक्रिया की सफल पुन: डिज़ाइन की स्वीकृति के रूप में महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार इस बात को मान्यता देता है कि सार्थक डिजिटल शासन केवल मौजूदा प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत करने के बारे में नहीं है; यह उन्हें सरल, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन करने के बारे में है।

भारत की व्यापक डिजिटल इंडिया यात्रा ने दिखाया है कि जब मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता हो, तो तकनीक सार्वजनिक सेवा अदायगी को बदल सकती है। डिजिटल पहचान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से लेकर ऑनलाइन कराधान और स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफार्मों तक, देश ने शासन में तकनीक की भूमिका का लगातार विस्तार किया है। अब उपभोक्ता न्याय भी उन क्षेत्रों की सूची में शामिल हो गया है, जिसमें संरचनात्मक डिजिटल सुधार हो रहे हैं।

'ई-जागृति' की सफलता भविष्य के शासन सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। डिजिटल प्लेटफार्मों को संस्थाओं के बजाय नागरिकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। पहुंच को बाद में सोची जाने वाली बात के बजाय एक मूल सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निष्पक्षता से समझौता किए बिना पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, तकनीक को न्याय को सरल बनाना चाहिए, न कि उसमें जटिलता की नई परतें जोड़नी चाहिए।

जैसे-जैसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, उपभोक्ता का विश्वास उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर अधिक निर्भर करेगा, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं। प्रभावी विवाद समाधान अब केवल एक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं रहा; यह एक आर्थिक आवश्यकता बन गया है, जो बाजारों में भरोसे को मजबूत करता है और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ई-जागृति प्लेटफार्म दिखाता है कि सोच-समझकर किया गया डिजिटल बदलाव कानूनी इरादे और नागरिक अनुभव के अंतर को कम कर सकता है। उपभोक्ता न्याय को तेज़, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाकर, यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत को मजबूत करता है कि डिजिटल लोकतंत्र में, न्याय तक पहुंच भी सेवा तक पहुंच जितनी ही सहज होनी चाहिए। यही शायद इक्कीसवीं सदी में ग्राहक देवो भव का सबसे सार्थक रूप है।

लेखक केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं

सवाल नैतिकता और जवाबदेही का भी है

विश्वनाथ सचदेव

दिल्ली में जंतर-मंतर पर, और देश में कई अन्य शहरों में भी, परीक्षाओं में हुई धांधली के आरोप में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है भाजपा-विरोधी दल स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों। पर इससे स्थिति की गंभीरता और भयावहता कम नहीं हो जाती।

यह सही है कि 'कॉकरोच पार्टी' द्वारा चलाये जा रहे देश के शिक्षामंत्री-विरोधी अभियान में दिल्ली के जंतर-मंतर में उतने युवा इकट्ठा नहीं हो रहे, जितनों की आयोजकों को आशा थी, पर सही यह भी है कि देश के युवाओं के संदर्भ में इस अभियान को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। युवा देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 'नीट' और 'सीबीएससी' जैसी परीक्षाओं में हो रही धांधली शिक्षामंत्री की असफलता का प्रतीक है। 'नीट' की परीक्षा के संदर्भ में देश के पंद्रह से अधिक युवाओं द्वारा की गई आत्महत्याएं निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है और इस बारे में सरकार की लगभग चुप्पी पर सवाल उठने ही चाहिए। सवाल उठ भी रहे हैं, पर जिन्हें जवाब देने हैं वे बचाव के रास्ते खोज रहे हैं।

ऐसा ही एक रास्ता शिक्षामंत्री ने खोजा है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन से बचाव के लिए देश में आपातकाल लागू करने का रास्ता खोजा था। बावजूद इसके कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने यह दावा किया था कि उसका यह कदम देश के संविधान द्वारा दिये गये अधिकार के अनुकूल था, आपातकाल लागू करने की यह कार्रवाई देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाली थी। देश के शानदार जनतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय था यह। तत्कालीन सरकार द्वारा अपने उठाये गये इस कदम के बचाव में बहुत कुछ कहा गया था, पर इसका औचित्य सिद्ध करने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता था।

स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपनी गलती का अहसास हो गया था। आपातकाल लागू करने के इक्कीस महीने बाद, मार्च 1977 में उन्होंने अपना उठाया गया कदम वापस ले लिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी भी थी। कांग्रेस के अब के नेता, राहुल गांधी ने भी उस घटना के लगभग पचास साल बाद, 2021 में, आपातकाल लागू करने को 'गलती' मानकर खेद व्यक्त किया था। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद भी यह कलंक तो कांग्रेस के माथे पर लगा ही रहा कि उसने आपातकाल लागू करके एक जनतंत्र-विरोधी कार्रवाई की थी। कांग्रेस के विरोधी दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, अक्सर कांग्रेस के इस 'काले कारनामे' का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं। अपने बचाव में कांग्रेस इस 'गलती' को भुला देने की बात कहती रही है। पर कांग्रेस-विरोधी इसे एक हथियार की तरह काम में लेते रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने आपातकाल की बरसी के अवसर पर, इस हथियार को अपने बचाव का साधन बनाने की कोशिश की है। अपने खिलाफ चल रहे 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो' आंदोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने कांग्रेस को 'जनतंत्र-विरोधी' बताकर अपना बचाव किया है। इसी संदर्भ में 'एनसीईआरटी' की किताबों में आपातकाल के बारे में जोड़े गये अध्याय का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को, और भावी पीढ़ियों को, आपातकाल की जानकारी देना ज़रूरी है। अब पहली बार कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की किताब में इसे 'भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियों' के रूप में शामिल किया गया है।

हालांकि 12वीं की किताब में पहले ही यह विषय जोड़ा जा चुका था, और जब यह जोड़ा गया तब सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। ऐसे में इस विषय को उठाकर शिक्षामंत्री आखिर क्या पाना चाहते हैं? शायद 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हो रही अपनी आलोचना से ध्यान बंटाने की एक कोशिश हो यह। शायद उन्हें लग रहा हो कि इस तरह ध्यान बंटा कर वे अपना कुछ बचाव करने में सफल हो सकते हैं!

'एनसीईआरटी' की नौवीं कक्षा की किताबों में भी आपातकाल का अध्याय जोड़ने का बचाव करते हुए शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां यह जान और समझ सकें कि ऐसा कोई काला अध्याय कभी लिखा गया था। भविष्य में ऐसा कुछ न हो इसके लिए आज के विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाना ज़रूरी है निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों को ऐसी बातों का पता होना चाहिए। 'एनसीईआरटी' की किताब में ऐसे अध्याय का होना कतई गलत नहीं है। गलत यह है कि ध्यान बंटाने के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 'नीट' और 'सीबीएससी' की परीक्षाओं में हो रही धांधली की जांच की दुहाई दी जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, इसका आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल किसी के ज़िम्मेदारी लेने का भी है। सवाल नैतिकता का भी है। नैतिकता का तकाज़ा है कि पर्चों की गड़बड़ी के चलते हुई आत्महत्याओं की ज़िम्मेदारी कोई तो ले। सन् 2021 से लेकर 2026 के बीच इस संदर्भ में 93 छात्रों की आत्महत्याओं के मामले सामने आये हैं। इसी वर्ष, यानी 2026 में, कम से कम चौदह छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर कोई तो ज़िम्मेदार होगा इन घटनाओं के लिए। दिल्ली में जंतर-मंतर पर, और देश में कई अन्य शहरों में भी, परीक्षाओं में हुई धांधली के आरोप में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है भाजपा-विरोधी दल स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों।

अलनीनो से निपटने को बने दीर्घकालीन रणनीति

ज्ञानेंद्र रावत

मानसून की सुस्त चाल से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल उपलब्धता पर व्यापक असर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी मानना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से घरेलू आर्थिकी और मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर दबाव पड़ेगा। अलनीनो के शुरुआती संकेत मानसून पर दिखाई देने लगे हैं। देखा जाये तो मानसून की रफ्तार धीमी होने की वजह से देश में कुछ समय पहले तक सूखे जैसे हालात का अंदेशा बढ़ने लगा था। अक्सर जून के तीसरे हफ्ते तक देश के बड़े हिस्से को मानसून सामान्यत: कवर कर लेता है। लेकिन पिछले पखवाड़े से इसकी गति ठहरी होने का सीधा-सीधा असर बारिश पर पड़ा है जिसका नतीजा देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर सूखे जैसे हालात दिखाई दिए थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एएफओ ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अलनीनो का भारत सहित एशिया के कई देशों की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ सकता है। खासकर भारत में धान और मक्का जैसी वर्षा आधारित फसलों के उत्पादन पर खासा असर पड़ सकता है। आशंका है कि अलनीनो के प्रभाव के चलते भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ऐसे हालात में खेती के लिए जरूरी नमी में कमी आयेगी। यही नहीं इसका असर वैश्विक खाद्य बाजारों और कीमतों पर पड़ेगा।

एएफओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर-लेस्ते जैसे देशों पर इसकी

अत्यधिक मार पड़ेगी। इन देशों पर सूखे की मार का खतरा बढ़ सकता है। इससे इन देशों की कृषि पर आधारित लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। स्काईमेट की मानें तो फिलहाल देश के लगभग आधे हिस्से में बारिश की भारी कमी है।

दरअसल, अलनीनो प्रभाव से प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगता है। भारत में इसका असर कमजोर मानसून और कम बारिश से जोड़ा जाता है। इतिहास इस बात का सबूत है कि ऐसी स्थिति में भारत में मौसमी बारिश न केवल कम हुई है बल्कि उसकी असमानता भी खतरनाक स्थिति तक बढ़ी है। आमतौर पर मानसून में ब्रेक की यह स्थिति अक्सर जुलाई या अगस्त में दिखाई देती है लेकिन इस बार मानसून की यह सुस्त रफ्तार चिंता का विषय है। इसकी अहम वजह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किसी मजबूत मौसम प्रणाली का विकसित न हो पाना है।

दरअसल, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव वाले क्षेत्र और चक्रवात मानसून को मजबूती देते हैं और उसे दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फिर अरब सागर में लो लेवल जेट भी पर्याप्त रूप से विकसित न हो पाना भी इसकी अहम वजह है। चिंताजनक है कि अलनीनो का सबसे बड़ा असर बारिश की वितरण व्यवस्था पर पड़ता है। असलियत यह है कि कई बार कुल बारिश बहुत कम नहीं होती लेकिन उसका समय और क्षेत्रीय वितरण असंतुलित हो जाने से विभिन्न राज्यों में बुआई, अंकुरण और फसल की शुरुआती बढ़ोतरी पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता उन इलाकों को लेकर है कि जहां अब भी खेती बारिश पर ही निर्भर है। फिर देश के लगभग आधे से अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। वहां किसानों की सारी उम्मीद बारिश पर ही टिकी होती है। सच्चाई यह है कि तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है।

इतना ही नहीं, जल भंडारण पर भी असर साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक देश के कुल 166 प्रमुख जलाशयों में कुल क्षमता का केवल 27.5 फीसदी पानी ही उपलब्ध है। यदि मानसून की सुस्ती लम्बे समय तक बनी रहती है तो पेयजल और सिंचाई दोनों मोर्चों पर दबाव काफी बढ़ जायेगा। निस्संदेह, मानसून की सुस्त चाल से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल उपलब्धता पर व्यापक असर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का भी मानना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से घरेलू आर्थिकी और मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर दबाव पड़ेगा। यही नहीं अलनीनो का खतरा छोटी राशि का कर्ज देने वाले संस्थानों के लिए ऋण वसूली को भी प्रभावित कर सकता है। क्रिसिल की रिपोर्ट का कहना है कि परिवारों के खर्च करने योग्य नगदी में कमी बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है।

मौसम विज्ञानी अलनीनो की स्थिति हाल-फिलहाल भले ज्यादा गंभीर न मानें लेकिन आसन्न खतरे को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अलनीनो के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल अलनीनो का खतरा केवल मौसम का मुद्दा नहीं है, बल्कि कृषि,उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। यही वजह है सरकार हर तरह की तैयारी रखने पर जोर दे रही है। सरकार की रणनीति कम बारिश होने की स्थिति से मुकाबला हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने की है। यही कारण है कि सरकार ने राज्यों से स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर फसल योजना बनाने, कम पानी में बेहतर उपज देने वाली फसलों को बढ़ावा देने और किसानों तक समय पर वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने के लिए कहा गया है।

यही नहीं, अलनीनो के असर के कारण आपूर्ति में आने वाली किसी भी समस्या या कीमतों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकार ने एक रणनीतिक सुरक्षा कवच तैयार किया है। सरकार के पास 43 लाख टन रिकार्ड दलहन का भंडार है। सरकार का मानना है कि यदि अलनीनो से खरीफ की फसल की बुआई प्रभावित होती है तो दलहन के इस सुरक्षित भंडार का इस्तेमाल किया जायेगा। अक्सर देखा गया है सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन जब अमल का समय आता है तो सरकारी अमले के हाथ फूल जाते हैं। जरूरत है ईमानदारी, संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई की, तभी हम अलनीनो जैसे इस गंभीर संकट का मुकाबला करने में समर्थ हो सकते हैं।

लेखक पर्यावरणविद् हैं।

यह सोना आखिर कैसा सोना है

अब लखीमपुर खीरी पुलिस तो यही कह रही है कि सोना पानी से खराब हो गया और जब उसे छत पर सुखाया तो बचे-खुचे को बंदर उठा ले गए। यह चूहे और बंदर जैसे जीव-जंतु सरकार और पुलिस के बड़े काम आते हैं जी सचमुच। सोने की ऐसी दुर्गत हो जाएगी, सचमुच सोचा न था जी। नहीं जी नहीं, इसके लिए प्रधानमंत्री कतई जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने तो एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह देकर उसका महत्व ही बयान किया था। नजर थोड़े ही लगाई थी।

नहीं जी नहीं, राम मंदिर के चढ़ावा चोर भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बेशक वहां से चढ़ावे की नकदी के साथ ही साथ सोना-चांदी के गहने, मुकुट आदि भी गायब होने के आरोप हैं। सोने की यह दुर्गत तो अभी लखीमपुर खीरी में हुई बताते हैं जी। वैसे लखीमपुर खीरी ने एक जमाने बड़ा नाम कमाया था, जब बताते हैं कि एक नेतापुत्र ने चार-पांच आंदोलनकारी किसानों को अपनी थार से कुचल डाला था। उसके बाद से थार ने भी बड़ा नाम कमाया है। खैर, यह तब की बात है जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। सो, लखीमपुर खीरी ऐसी भी कोई अनजान जगह नहीं है।

नेतापुत्र उसे काफी प्रसिद्धि दिला चुके हैं। पर जी, यह सोना ऐसा कैसा सोना है कि बताओ बारिश में खराब हो गया। एक जमाने में लोग अपने सोने के गहने-जेवर और गिन्नियां मिट्टी में, जमीन में ही दबाकर रखते थे और बरसों बाद भी जब वह खजाना किसी के हाथ लगता था, तो ज्यों का त्यों मिलता था। कभी किसी ने शिकायत नहीं कि सोना मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। बारिश से डरने वाले इंसानों तक को इस तरह के ताने सुनने मिल जाते हैं कि अबे मिट्टी का थोड़े ही बना है कि गल जाएगा। पर यह सोना तो एकदम ही मिट्टी निकला जी, जो बारिश से गल गया और गलकर बह गया। माना कि पुलिस के सामने इंसान भी भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन सोना मिट्टी कैसे बन गया यार। अब लखीमपुर खीरी पुलिस तो यही कह रही है कि सोना पानी से खराब हो गया और जब उसे छत पर सुखाया तो बचे-खुचे को बंदर उठा ले गए। यह चूहे और बंदर जैसे जीव-जंतु सरकार और पुलिस के बड़े काम आते हैं जी सचमुच। चूहे अगर गोदामों में रखा सरकार का राशन चट कर जाते हैं तो वे पुलिस के मालखाने में रखी शराब भी पी जाते हैं। जी, यह कपोल कल्पना नहीं है, इसके प्रमाण हैं।

खेद की बात यह है कि सरकार और पुलिस की मदद करने वाले इन चूहों को अभी तक कोई इनाम-इकराम नहीं मिला है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर बीएसपी प्रबंधन ने दी भावभीनी विदाई

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की सेवा से जून माह 2026 में कुल 86 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया, जिसमें खदान बिरादरी के 05 व संयंत्र के 81 गैर-कार्यपालक शामिल हैं। 04 जुलाई 2026 को भिलाई निवास में आयोजित समारोह में संयंत्र के गैर-कार्यपालकों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन- संकार्य) जे. एन ठाकुर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजय द्विवेदी, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन-कर्मचारी सेवाएं) मनीष पंत और उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एससीसीए) राजेंद्र प्रसाद ने कार्मिकों को सेवानिवृत्ति आदेश प्रदान किया। गणमान्य अतिथियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें स्वस्थ एवं सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अंत में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन के नए पड़ाव के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। संयंत्र प्रबंधन ने विदा होने वाले इस्पात बिरादरी के सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सुप्रियो सेन ने किया।

सेवा सेतु पोर्टल से हितग्राहियों को घर बैठे ऑनलाईन प्राप्त हुए जनजातीय प्रमाण-पत्र

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल सुशासन पहल 'सेवा सेतु' प्रदेश के नागरिकों तक सीधे सरकारी सुविधाएँ पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी है, जिससे आमजन को अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी तारतम्य में, डिजिटल सशक्तिकरण की एक प्रभावी झलक दुर्ग जिले के ग्राम बोरई में देखने को मिली, जहाँ विगत 3 जुलाई 2026 को आवेदित दो हितग्राहियों, जय ठाकुर और यमुना ठाकुर का सामाजिक प्रास्थिति (अनुसूचित जनजाति-गोड़) प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी हरवंश सिंह मिरी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत कर ऑनलाइन जारी किया गया। बिना किसी दफ्तर जाए, घर बैठे आईटी नियमों के तहत प्राप्त हुए ये डिजिटल दस्तावेज़ यह पुख्ता प्रमाण हैं कि 'सेवा सेतु' व्यवस्था दूर-दराज के इलाकों में भी बेहद पारदर्शी, त्वरित और जन-अनुकूल तरीके से काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि 'सेवा सेतु' छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक डिजिटल सेवाएँ लाने की एक ऐसी खास पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से दूर-दराज विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों तक सरकार की योजनाएँ और सुविधाएँ पहुँचाना है। राज्य सरकार की इस डिजिटल पहल के तहत लगभग 36 विभागों की 528 सेवाएँ एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस नई डिजिटल व्यवस्था के शुरू होने से अब हितग्राहियों का समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है, साथ ही उन्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी से जुड़े जरूरी प्रमाण-पत्र पाने के लिए दलालों और बिचौलियों से भी पूरी तरह मुक्ति मिल गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों हेतु वेल्थ मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विभाग द्वारा 03 जुलाई 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास केन्द्र के सभागार में वेल्थ मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रभावी वित्तीय नियोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैनेजमेंट जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजय द्विवेदी रहें।

इस अवसर पर कुल 103 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में विशेष रूप से 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत वित्तीय नियोजन एवं संपत्ति प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जे.एन. ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र एक्सिस बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को वित्तीय नियोजन, निवेश रणनीतियाँ, सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण, कर-बचत निवेश विकल्प तथा प्रभावी वेल्थ मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए समय रहते वित्तीय योजना बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में संजय द्विवेदी ने कर्मचारियों को वित्तीय रूप से जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विशेषकर सेवानिवृत्ति के निकट पहुँच रहे कर्मचारियों के लिए सुनियोजित वित्तीय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु इस प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्मिक विभाग की सराहना की।

कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) मिहिर मनोहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।

दुर्ग के बैधनाथ पारा में नाली निर्माण के शिकायत पर महापौर का औचक निरीक्षण

ठेकेदारों को कड़ी फटकार, सुधार नहीं होने पर काम रोकने व ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 38, बैद्यनाथ पारा स्थित महावीर कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 15-15 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन दो नाली निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिलने पर महापौर अलका बाघमार ने लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, क्षेत्रीय पार्षद रामचंद्र सेन, अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों के साथ स्थल का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, गहराई, चौड़ाई तथा उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री का बारीकी से परीक्षण कराया। स्थानीय नागरिकों द्वारा नाली निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत पर उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली तथा निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए।

लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने स्वयं टेप से नालियों की नाप-जोख कराई। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं ठेकेदारों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजीव झा तथा संबंधित ठेकेदारों को सख्त फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि निर्माण कार्य में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो कार्य रोकने के साथ-साथ संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक विकास कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही, अनियमितता या मानकों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महापौर ने संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार राजू झा एवं मनीष सोनी और राहुल सिंह के विरुद्ध आवश्यक जांच के लिए सैंपल लेकर लैब भेजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद जिस फर्म के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा पाया जाएगा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी निर्माण कार्य में बरती जा रही कथित अनियमितताओं से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान पार्षद रामचंद्र सेन, पार्षद रंजीता पाटिल, पार्षद सुरूचि उमरे, पार्षद सावित्री दमाहे,ललिता ठाकुर, कार्यपालन अभियंता मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, उप अभियंता मोहित मरकाम सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

विधायक रिकेश ने दी तीजन बाई को श्रद्धांजलि

बोले- स्वर थम गया, लेकिन तीजन की गूंज सदियों तक रहेगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण एवं सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हुआ है। तीजन बाई का स्वर भले ही मौन हो गया हो, लेकिन उनकी पंडवानी की गूंज आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की सांस्कृतिक दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है।

विधायक सेन ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी ओजस्वी आवाज़, अद्भुत अभिनय और बेमिसाल प्रस्तुति से पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उन्होंने पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति से परिचित कराया और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि वर्ष 2023 में तीजन बाई को लकवे (पैरालिसिस) का दौरा पड़ा था। उस समय उनका परिवार इलाज के भारी खर्च और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। इतना ही नहीं, उनकी आठ महीने की पेंशन भी लंबित थी। जैसे ही यह जानकारी विधायक रिकेश सेन तक पहुंची, उन्होंने तत्काल राज्य सरकार और प्रशासन से चर्चा कर पेंशन सहित अन्य आवश्यक सहायता दिलाने की पहल की। साथ ही मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए अपने विधायक मानदेय से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी तीजन बाई के इलाज के लिए प्रदान की।

विधायक रिकेश ने कहा कि हमारी संस्कृति की धरोहरों का सम्मान केवल पुरस्कारों से नहीं, बल्कि कठिन समय में उनके साथ खड़े होकर किया जाता है। तीजन बाई जैसी महान विभूतियां सदैव हमारी प्रेरणा रहेंगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

निगम आयुक्त का जोन-5 में औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-5 क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्यान, क्रिकेट कोर्ट, पेवर ब्लॉक, सफाई व्यवस्था, यात्री प्रतीक्षालय और टेनिस कोर्ट की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

निगम आयुक्त ने सेक्टर-10 स्थित उद्यान का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई और पेवर ब्लॉक की स्थिति देखी। उन्होंने पार्क की सुंदरता और सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। वहीं समीप स्थित क्रिकेट कोर्ट का निरीक्षण कर जाली और नेट की

मरम्मत जल्द कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान सड़क क्रमांक-5 पर रोड किनारे लगे पेवर ब्लॉकों की स्थिति भी देखी गई। लंबे समय से उपयोग में होने के कारण कई स्थानों पर पेवर ब्लॉक उखड़ गए हैं, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। आयुक्त ने संबंधित एजेंसी के माध्यम से इनका तत्काल संधारण कराने के निर्देश दिए।

जोनल मार्केट के पास स्थित कचरा डंपिंग प्वाइंट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि पिछले कुछ दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है। आयुक्त ने कचरे का तत्काल उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके।

इसके अलावा सड़क क्रमांक-11 स्थित दुर्गा पूजा मैदान के पास बने यात्री प्रतीक्षालय का निरीक्षण कर वहां लगी कुर्सियों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। सड़क क्रमांक-13 और 14 के समीप स्थित टेनिस कोर्ट का भी निरीक्षण किया गया, जहां आवश्यक संधारण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय गौर, स्थानीय पार्षद अभय सोनी, सहायक अभियंता श्वेता महेश्वर, उप अभियंता शंकर सुमन मरकाम, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 'सेव अ लाइफ' सीपीसीआर कार्यशाला आयोजित

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग द्वारा विगत दिनों में 'सेव अ लाइफ' पहल के अंतर्गत मासिक 'हैंड्स-ओनली सीपीसीआर (कार्डियो पल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन) प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जन-जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में आपातकालीन हृदयाघात की स्थिति में त्वरित जीवनरक्षक सहायता प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक लोगों को सीपीसीआर तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है।

यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यशाला में एक प्रतिभागी ने अपने वास्तविक जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार कार्यस्थल पर एक सहकर्मी को अचानक हृदयाघात आने पर उन्होंने प्रशिक्षण से प्राप्त सीपीसीआर तकनीक का समय पर प्रयोग कर उसका जीवन बचाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रेरक अनुभव ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को भावुक एवं प्रेरित किया तथा यह संदेश दिया कि सीपीसीआर केवल एक चिकित्सकीय तकनीक नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन बचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा प्रशिक्षण मैनिकिन पर सीपीसीआर का अभ्यास किया। एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं डीएनबी रेजिडेंट्स ने प्रत्येक प्रतिभागी को सही तकनीक, शरीर की उचित स्थिति तथा प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन की विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

भिलाई शाखा ने मनाया सीए सप्ताह 2026, विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 78वें स्थापना दिवस (सीए दिवस) के उपलक्ष्य में भिलाई शाखा द्वारा 27 जून से 1 जुलाई 2026 तक 'सीए सप्ताह 2026' का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। सप्ताहभर चले इस आयोजन में उद्यमिता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य जागरूकता, रक्तदान, वित्तीय साक्षरता, करियर मार्गदर्शन, खेलकूद एवं सामाजिक सेवा से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

27 जून को आयोजित ICAI MSME महोत्सव के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में CA Dinesh Andani, एसके सिंह (महाप्रबंधक, DTIC), प्रतिपाल वहाने (उप महाप्रबंधक, MSME Technology Centre) तथा श्री विवेक राय (Chief Manager-SME, SBI) ने उद्यम स्थापना, वित्तीय सहायता, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, तकनीकी नवाचार एवं व्यवसाय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

28 जून को आयोजित Wellness, Care & Fun Carnival के अंतर्गत भिलाई शाखा के पदाधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से 60 प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। इसके

पश्चात GT Diagnostics °ß´ Titan Eye के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 40 से 50 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी दिन जिला चिकित्सालय, भिलाई के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। साथ ही शतरंज, कैरम एवं चाइनीज़ चेकर्स जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें लगभग 40 से 50 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

30 जून को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत गांधी विद्यापीठ, भिलाई में विद्यार्थियों को वित्तीय अनुशासन, बचत, निवेश, डिजिटल भुगतान एवं कर जागरूकता विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में CA प्रभजीत सिंह एवं CA प्रतीक अग्रवाल ने विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के महत्व से अवगत कराया। इसी क्रम में श्री शंकरा स्कूल Sector-10 में लगभग 200 विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें CA राहुल बत्रा ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों, परीक्षा प्रणाली एवं व्यावसायिक संभावनाओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

1 जुलाई को 78वें सीए दिवस के अवसर पर भिलाई शाखा परिसर में शाखा के पदाधिकारियों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपस्थिति में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इसके पश्चात वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान तथा ब्लाइंड स्कूल में सेवा गतिविधि आयोजित कर समाज के प्रति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सामाजिक प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। सम्पूर्ण सीए सप्ताह 2026 का सफल संचालन CAअमित राय एवं CA अरविंद सुराणा के मार्गदर्शन में किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी CA अनिल झावर, CA अमित कोचर, CAआनंद दीक्षित, CAआनंद जिमनानी , CAदिनेश अंदानी एवं CA राम स्वरूप तथा CA राकेश धोबे ने निभाई।

इस अवसर पर ब्रांच चेयरमैन सुखदेव राठी,सचिव प्रतीक अग्रवाल, प्रभजीत सिंग पूर्व चेयरमैन एक्सयूकुटिव मेम्बर सी ए राजेश कुमार बाफना तथा CICASA चैयरमैन तलविंदर ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं एवं आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीए सप्ताह का उद्देश्य केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज सेवा, जनजागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना मीडिया प्रभारी शंकर सचदेव ने दी।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को घर बैठे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल सुशासन पहल 'सेवा सेतु' प्रदेश के नागरिकों तक सीधे सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी है, जिससे आमजन को अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी तारतम्य में, डिजिटल सशक्तिकरण की एक प्रभावी झलक दुर्ग जिले के ग्राम बोरई में देखने को मिली, जहाँ विगत 3 जुलाई 2026 को आवेदित दो हितग्राहियों, जय ठाकुर और यमुना ठाकुर का सामाजिक प्रास्थिति (अनुसूचित जनजाति-गोंड) प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी हरवंश सिंह मिरी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत कर ऑनलाइन जारी किया गया। बिना किसी दफ्तर जाए, घर बैठे आईटी नियमों के तहत प्राप्त हुए ये डिजिटल दस्तावेज़ यह पुख्ता प्रमाण हैं कि 'सेवा सेतु' व्यवस्था दूर-दराज के इलाकों में भी बेहद पारदर्शी, त्वरित और जन-अनुकूल तरीके से काम कर रही है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विद्यासागर साहू ने अपनाई स्वच्छ ऊर्जा

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला निवासी विद्यासागर साहू ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किया है। इससे वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तथा भविष्य में बिजली खर्च में बचत का लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यासागर साहू ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदन कर अपने घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया। योजना का बैंकिंग प्रक्रिया छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक भरेंगांव शाखा से पूरी हुई। योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन से 30 हजार रूपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई है।

पशु सखी बन आत्मनिर्भर हुईं तैलासो राजवाड़े, हर माह 10 से 15 हजार रुपये की आय

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। इसी का प्रेरक उदाहरण सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर की तैलासो राजवाड़े हैं, जो महादेव स्वयं सहायता समूह, रोशनी ग्राम संगठन (वीओ) एवं समृद्ध सरगुजा संकुल से जुड़ी हुई हैं। वे पिछले दो वर्षों से पशु सखी के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। तैलासो राजवाड़े बताती हैं कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें आजीविका का सशक्त माध्यम मिला। वर्तमान में वे पशुपालकों को बकरियों की देखभाल, टीकाकरण के प्रति जागरूकता, समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाइयों की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इस कार्य से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 से 15 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण एवं बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा कक्षा 12वीं, दूसरा कक्षा 10वीं तथा सबसे छोटा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है। लेकिन आज स्वयं की आय से वे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हैं।

मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की बोआई-रोपाई : कृषि वैज्ञानिक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में इस वर्ष मानसून सामान्य से कुछ देर से पहुंचा है, लेकिन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी भी धान की खेती के लिए पर्याप्त समय है। मौसम को देखते हुए किसानों को कुछ जरूरी कृषि सलाह जारी की गई है।

वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून लगभग 10 दिन देर से आया। जून माह में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई, लेकिन अब प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई तक राज्य में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि किसान 15 जुलाई तक धान की सीधी बुआई तथा 30 जुलाई तक रोपाई और बियासी का कार्य कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश थोड़ा विलंब भी हो जाए और हरेली (12 अगस्त) तक बोआई-रोपाई करनी पड़े, तब भी फसल पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।

मानसून में देरी को देखते हुए किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, जैसे इन्द्रावती, बस्तर धान-1, छत्तीसगढ़ बारानी धान, इंदिरा एरोबिक धान, एमटीयू-1010, एमटीयू-1153, एमटीयू-1156, एमटीयू-1001, छत्तीसगढ़ धान-1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान और महामाया का उपयोग करने की सलाह दी गई है। किसानों से कहा गया है कि बुआई से पहले बीज का फफूंदनाशक दवा से उपचार अवश्य करें और जैव उर्वरकों का भी उपयोग करें। इससे फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन बढ़ता है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि धान की सीधी बुआई में खरपतवार (खरपतवार/घास) बड़ी समस्या होती है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए बुआई के बाद पहले 40 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। इसके लिए हाथ से निंदाई, पैडी वीडर या कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित खरपतवारनाशकों का उपयोग किया जा सकता है।

उर्वरक प्रबंधन को लेकर किसानों को सलाह दी गई है कि प्रति एकड़ अधिकतम दो बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी का ही उपयोग करें। डीएपी की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई के समय दें, जबकि यूरिया की पहली खुराक 30 से 35 दिन बाद और दूसरी खुराक 60 से 70 दिन बाद दें। साथ ही हरी खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि राज्य की प्राथमिक कृषि साख समितियों में किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, एनपीके, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसानों को आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान सेवाओं के संचालक डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी ने किसानों से अपील की है कि खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें।

समाज में डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण - राज्यपाल डेका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने महाराष्ट्र मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में समाज के युवा डॉक्टरों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक भवन की ओर से महाराष्ट्र मंडल को प्रदत्त एंबुलेंस का लोकार्पण भी किया।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही समाज के विकास और प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। डॉक्टर मानव जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े होते हैं, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट उद्योग, व्यापार और व्यवसाय को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा एक नोबल व्यवसाय है, जो केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च दायित्व है। मरीज डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानता है, इसलिए चिकित्सकों की जिम्मेदारी अत्यंत गंभीर है। कठिन परिश्रम और अपने अभिभावकों के सहयोग से डॉक्टर बनने वाले युवाओं को सेवा भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की जिम्मेदारी केवल अस्पताल तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह 24 घंटे समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता है।

राज्यपाल ने चिकित्सकों से कहा कि आधुनिक जांच रिपोर्टों के आधार पर उपचार आवश्यक है, लेकिन मरीज का प्रत्यक्ष परीक्षण और उससे आत्मीय संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे मरीज को मानसिक संतोष मिलता है और चिकित्सक के प्रति उसका विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्ग मरीजों के प्रति संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय व्यवहार अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में आज जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है, उसका श्रेय मानव की बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और निरंतर नवाचार को जाता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका पर राज्यपाल ने कहा कि आज उनके कार्य का दायरा काफी व्यापक हो गया है। वे केवल लेखा-जोखा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यवसायियों के मार्गदर्शक और मेंटर की भूमिका भी निभाते हैं। व्यवसाय का विस्तार कैसे किया जाए, स्टार्टअप कैसे स्थापित किया जाए तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक युवा पारिवारिक व्यवसाय को अपेक्षित महत्व नहीं देते और उसमें संभावनाएं कम देखते हैं, जबकि सही सोच, नवाचार और उचित मार्गदर्शन से पारिवारिक व्यवसाय को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठजन, महिलाएं, युवा तथा बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे।

46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी आवंटन से खरीफ सीजन के लिए खाद की उपलब्धता हुई सुनिश्चित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा छत्तीसगढ़ को 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी आवंटित किए जाने पर उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा के विशेष सहयोग से लिया गया यह निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि कुछ समय पूर्व नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा से हुई भेंट के दौरान उन्होंने खरीफ सीजन की आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के लिए अतिरिक्त डीएपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को अतिरिक्त डीएपी का आवंटन प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया की उपलब्धता पहले से ही पर्याप्त थी और अब अतिरिक्त डीएपी मिलने से खरीफ सीजन के लिए खाद की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। इससे किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा कृषि कार्य सुचारु रूप से संचालित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें समय पर डीएपी, यूरिया सहित सभी आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार अन्नदाता के कल्याण और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जशपुर में एचपीवी टीकाकरण अभियान तेज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जशपुर जिले में किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। यह विशेष अभियान 31 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसके तहत जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय में पात्र किशोरियों को नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. जात्रा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत ऐसी किशोरियां पात्र हैं, जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है। आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि प्रत्येक पात्र किशोरी को सहजता से इसका लाभ मिल सके। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बेटियों का स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है। शासन द्वारा यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए सभी पात्र किशोरियों का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया यह टीका भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर बेटियों के स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की मजबूत नींव रखता है। सीएमएचओ डॉ. जात्रा ने बताया कि एचपीवी टीकाकरण का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 28 फरवरी 2026 को किया गया था। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय मानी जाती है। समय पर टीकाकरण से भविष्य में इस गंभीर बीमारी का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले अन्य कैंसर तथा जननांग मस्सों से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल ला रही बदलाव, हरी खाद अपनाकर आत्मनिर्भर खेती की राह पर बढ़ रहे किसान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्राकृतिक, जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कृषि विभाग के मार्गदर्शन का सकारात्मक प्रभाव अब गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। किसान आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं।

इसी कड़ी में महासमुंद जिले के विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम बड़ेसाजापाली के प्रगतिशील किसान श्री हिमांशु बंजारे ने जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने 0.80 हेक्टेयर कृषि रकबे में ढैंचा की हरी खाद की फसल लगाई है। लगभग 30 दिन की हो चुकी इस फसल को निर्धारित समय पर खेत में पलटकर हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ेगी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी तथा आगामी फसलों की उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है।

हिमांशु बंजारे का कहना है कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती न केवल खेती की लागत को कम करती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी लंबे समय तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि ढैंचा जैसी हरी खाद वाली फसलों के उपयोग से खेतों में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है और उत्पादन अधिक टिकाऊ बनता है। उन्होंने अन्य किसानों से भी इस पद्धति को अपनाकर पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की अपील की।

उप संचालक कृषि एफआर. कश्यप ने बताया कि हरी खाद मिट्टी की उर्वरता और संरचना सुधारने का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। ढैंचा, सन, लोबिया, उड़द, मूंग और ग्वार जैसी दलहनी फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं तथा कम लागत में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। इन फसलों को फूल आने से पहले खेत में पलटने पर लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है।

उन्होंने बताया कि हरी खाद के नियमित उपयोग से मिट्टी भुरभुरी बनती है, जलधारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार बेहतर होता है तथा अम्लीय और क्षारीय भूमि के संतुलन में भी सुधार होता है। इसके साथ ही मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या और सक्रियता बढ़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। हरी खाद मृदा क्षरण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को टिकाऊ, कम लागत और पर्यावरण-अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, जागरूकता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक एवं जैविक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हिमांशु बंजारे जैसे प्रगतिशील किसानों की पहल इस बात का प्रमाण है।

तेजस कार्यशाला का हुआ सफल आयोजन, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा नया बाजार

स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को मिली नई दिशा, स्थानीय उत्पादों और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सुकमा जिले में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्वावधान में शबरी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय 'तेजस कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में नवाचार, एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी), फूड प्रोसेसिंग और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों, एमएसएमई उद्यमियों, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों सहित लगभग 350 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जिला पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर ने कहा कि सुकमा में कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक और नवाचार अपनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जिले के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कार्यशाला में देशभर से आए विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को स्टार्टअप इंडिया के तहत डीपीआईआईटी मान्यता, पंजीयन प्रक्रिया, सफल व्यवसाय मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) की विस्तृत जानकारी दी। बैंक अधिकारियों एवं इन्क्यूबेशन सेंटर के विशेषज्ञों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, वित्तीय सहायता, निवेश और व्यापार विस्तार की प्रक्रियाओं को सरल भाषा में समझाया।

प्रभारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री कैलाश कश्यप ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को केवल स्टार्टअप तक सीमित रखना नहीं, बल्कि कृषि, वनोपज, फूड प्रोसेसिंग और हस्तशिल्प आधारित उद्यमों से जोड़ना है। इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की। इस पहल से सुकमा में स्थानीय उद्यमिता को नई गति मिलने और जिले के उत्पादों को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष हूँगा राम मरकाम, पार्षद रंजीत बारठ, पूर्व योग आयोग सदस्य राजेश नारा, लीड बैंक अधिकारी विकास कुमार, रवि वाधवानी (एफ्मीआईआईटी), अरविंद कुमार (ईडीआई), बरगीन रसेल, अबुल हसन (स्टार्टअप टीम), तुलिका शर्मा (इन्क्यूबेटर, जगदलपुर), चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, पत्रकार संघ के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, कैम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

'मोटी या पतली हो जाओ', काजल अग्रवाल ने खूबसूरत दिखने के दबाव पर रखी राय

काजल अग्रवाल का मानना है कि पहले के मुकाबले अब अभिनेत्रियों पर खूबसूरत दिखने का ज्यादा दबाव है। उनका मानना है कि 'ना' कहना सीखना ज्यादा जरूरी है।

काजल अग्रवाल ने अभिनेत्रियों के परफेक्ट दिखने के दबाव को लेकर बात की है। उनका मानना है कि आज की एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में आने के लिए ज्यादा कड़ी जांच-परख का सामना करना पड़ता है। उन्होंने माना कि उन्हें उन युवा एक्ट्रेस के लिए बुरा लगता है जो इंडस्ट्री के खूबसूरती के पैमानों से जूझ रही हैं।

पहले दबाव कम था

काजल ने खूबसूरत दिखने के दबाव को लेकर कहा 'समय बहुत अलग था। सोशल मीडिया नहीं था। बाहरी तौर पर एक्स्ट्रा जजमेंट नहीं होते थे। ऐसे कोई एयरपोर्ट लुक नहीं थे, जिनके लिए आपको सफाई देनी पड़े। आप बस जैसे हैं, वैसे ही रह सकते थे और किसी कमरे या एयरपोर्ट में आराम से जा सकते थे। पूरी तरह तैयार होकर ट्रैवल करना आसान नहीं है। शक्र है कि उस समय मुझे इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा।'

युवा लड़कियों के लिए बुरा लगता है

काजल ने आगे कहा 'फिल्ममेकर्स की तरफ से जजमेंट जरूर आते थे, जैसे वे चाहते थे कि मैं मोटी या पतली दिखूं या कुछ और। ऐसी बातें होती थीं। मगर मुझे लगता है कि तब भी चीजें आसान थीं। तब इतना क्रूर माहौल नहीं था। इसलिए मुझे अभी की युवा लड़कियों के लिए बुरा लगता है। मुझे सच में उम्मीद है कि वे अपनी जगह बना पाएंगी।'

'ना' कहना सीखना जरूरी है

काजल ने यह भी कहा कि उनमें हमेशा उन स्थितियों से बाहर निकलने का आत्मविश्वास रहा है, जिनमें वे सहज नहीं थीं। उन्होंने कभी भी सिर्फ मौके पाने के लिए 'हां' कहने का दबाव महसूस नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बात पर सहमत होने के बजाय 'ना' कहना सीखना कहीं ज्यादा जरूरी है।

काजल का वर्कफ्रंट

काजल अभी अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। चेतन डीके के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पेस्टिसाइड (कीटनाशक) वाली खेती और समाज पर इसके असर को दिखाती है। यह 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

'आजकल एक रील से स्टार बन सकते हैं', दिव्या दत्ता ने बताया युवाओं की क्या हैं चुनौतियां?

दिव्या दत्ता को हाल ही में वेब सीरीज 'चिरैया' में एक ऐसी महिला का किरदार निभाने के लिए तारीफ मिली, जो अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाती है। हाल ही में दिव्या ने सोशल मीडिया के दौर में एक्टर्स के सामने आने वाली नई चुनौतियों, किरदार पर आधारित कहानियों पर स्टार सिस्टम के असर और दूसरी चीजों के बारे में बात की। दिव्या का मानना है कि आज के एक्टर्स के लिए नई चुनौती सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर का बढ़ना है।

युवा लाइक्स और वैलिडेशन के बीच फंसा है

दिव्या दत्ता ने सोशल मीडिया के दौर और नए एक्टर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर कहा कि जब मौकों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी, तब हमें कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि तब मौके और माध्यम कम थे। आजकल आप अपने लिए एक रील बना सकते हैं और अचानक स्टार बन सकते हैं। प्रोड्यूसर आप पर ध्यान देते हैं और कहते हैं, 'ठीक है, इस व्यक्ति को लेते हैं।' इस लिहाज से यह आसान हो गया है।

कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपने लिए मजबूत करियर बनाया है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। युवा पीढ़ी अब ऐसी स्थिति में फंसी हुई है जहां सब कुछ लाइक्स, वैलिडेशन और विजिबिलिटी के इर्द-गिर्द घूमता है।

मजबूत महिलाओं के किरदार बॉलीवुड में कम हैं

युवाओं की चुनौती को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि लोग असल में पलों को जीने के बजाय उन्हें रिकॉर्ड करने पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। उनका मानना है कि गहराई अभी भी मौजूद है। एक ऐसे इवेंट को याद करते हुए जहां दर्शकों ने उन्हें पूरी खामोशी से सुना, दिव्या ने कहा कि असली चुनौती उस दबाव में है जो युवाओं से कहता है कि पहले फॉलोअर्स लाओ, फिर तुम्हें काम मिलेगा।

'चिरैया' में हुई दिव्या की तारीफ

दिव्या दत्ता आखिरी बार 'चिरैया' में नजर आई थीं। मैरिटल रेप से जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित इस सीरीज को काफी पसंद किया गया और दिव्या की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई। यह सीरीज जीयोहॉटस्टार पर मौजूद है।

'क्रेडिट अहमद खान को देना होगा' रवीना टंडन ने 'वेलकम टू द जंगल' के निर्देशक को सराहा, को-एक्टर्स पर की ये बात

अहमद खान निर्देशित और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में रवीना टंडन ने भी अभिनय किया है। वह अहमद खान को एक खास बात के लिए सराहती हैं। जानिए, डायरेक्टर को लेकर क्या बोलीं रवीना टंडन।

अहमद खान निर्देशित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने 22 साल बाद साथ काम किया है। बता दें कि एक दौर था जब रवीना टंडन और अक्षय कुमार रिलेशनशिप में थे, फिर इनका ब्रेकअप हो गया। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना और रवीना ने अनिल थडानी से शादी की। एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ काम करने का अनुभव रवीना के लिए कैसा रहा? अहमद खान के निर्देशन को वह कैसे देखती हैं? और शूटिंग का एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा था? हालिया के एक इंटरव्यू में रवीना ने यह बातें साझा की हैं।

शूटिंग करना मजेदार गेट-टुगेदर जैसा था

आईएएनएस से की गई हालिया बातचीत में रवीना टंडन ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में कहा, 'फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया। वे मेरे पुराने दोस्त हैं। उनके साथ शूटिंग करना मजेदार गेट-टुगेदर जैसा था। काम करते-करते हमने एक अच्छी फिल्म बना ली। इतने बड़े और अनुभवी कास्ट को इतनी आसानी से संभालने का क्रेडिट अहमद खान को देना चाहिए।'

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए दिग्गज बॉलीवुड सितारे

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, दलेर मेहंदी और आफताब, जैकलीन फर्नांडिज, दिशा पाटनी जैसे कई एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म में कॉमेडियन कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक भी दिखाई दिए।

'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा हाल?

'वेलकम टू द जंगल' को सिनेमाघरों में आठ दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह फिल्म अब तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है।

मुंबई की लोकल ट्रेन में गुजरे मेरे संघर्ष के दिन : रिद्धि डोगरा

रिद्धि डोगरा उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम किया। अच्छी एक्टिंग की वजह से उन्हें शाहरुख खान जैसे बिग स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री की खास बात यह है कि वह आज सफल हैं। लेकिन, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद रखा है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में सफर करने के दिनों को याद किया।

उन्होंने उन मुश्किलों का जिक्र किया, जिनका उन्होंने सामना किया और उस दृढ़ संकल्प के बारे में बताया, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके रास्ते को आकार दिया। रिद्धि ने लिखा कि मुझे हमेशा से जुलाई का महीना पसंद रहा है। इन तस्वीरों ने जुलाई के पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं। जुलाई 2005 में मेरी मुंबई की कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज से नई-नई निकली थी और बड़ी दुनिया में पढने, घूमने-फिरने, जीने और सीखने के लिए उत्सुक थी। इसीलिए, मैंने मुंबई को चुना। यह एक ऐसा शहर है, जो अनजाने में मुझे लंबे समय से बुला रहा था। मुझे इस शहर की हलचल भरी जिंदगी और आकर्षण में सुकून मिलता है।

रिद्धि डोगरा ने लिखा कि लोकल ट्रेनें मेरी सबसे पसंदीदा जगह बन गई थीं। 2005 से 2007 के बीच मैं एक ही दिन में कई तरह के वाहनों से सफर करती थी। पहले कॉलेज जाती, फिर अपनी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी पर जाती। मैं पूरा समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए और अपने भविष्य के सपनों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती रहती थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं अपनी किस्मत की खुद मालिक थी।

आज जिसे हम विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वह मैं उन दिनों रोज करती थी। लोग उसे 'दिन में सपना देखना' कहते थे। इस दौरान एक गाना मेरे आईपॉड पर सबसे ज्यादा चलता था। रिद्धि डोगरा को असुर में नुसरत, ऑल्ट बालाजी की द मैरिड वुमन में आस्था, स्टार प्लस की मर्यादा: लेकिन कब तक? में प्रिया और वो अपना सा में निशा का किरदार निभाने के लिए पहचान मिली।

वह नच बलिए 6 और फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 6 जैसे लोकप्रिय रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। रिद्धि डोगरा द साबरमती रिपोर्ट, लकड़बग्घा, और जवान जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए जोड़ों के दर्द से जुड़े ये 5 चेतावनी भरे संकेत

जोड़ों से जुड़ी समस्याएं आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही हैं, खासकर महिलाओं में यह आम हो गई हैं। कई बार महिलाएं जोड़ों का दर्द जैसे संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे चेतावनी भरे संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इन संकेतों को पहचानकर आप समय पर इलाज करा सकती हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं।

सुबह उठते ही जोड़ों में अकडऩ होना

अगर आपको सुबह उठते ही अपने हाथों या पैरों में अकडऩ महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह गठिया या अन्य किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय पर इलाज मिल सके। सुबह की अकडऩ अक्सर उम्र बढऩे, असंतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होती है। सही समय पर पहचान और इलाज से आप इस समस्या से बच सकती हैं।

बैठते या उठते समय दर्द होना

बैठते या उठते समय अगर आपको दर्द होता है तो इसे हल्के में न लें। यह भी गठिया या अन्य किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। बैठते या उठते समय दर्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत तरीके से बैठना, शारीरिक गतिविधियों की कमी या चोट का सही इलाज न होना। सही समय पर इलाज से आप इससे बच सकती हैं।

चलने में दिक्कत होना

अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। चलने में दिक्कत होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे जोड़ों का कमजोर होना, पुराने चोट का सही इलाज न होना या शारीरिक गतिविधियों की कमी। सही समय पर पहचान और इलाज से आप इस समस्या से बच सकती हैं।

रात में सोते समय टांगों में दर्द होना

रात के समय सोते समय अगर आपकी टांगों में दर्द होता है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। रात के समय सोते समय दर्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत गद्दे या तकिए का इस्तेमाल, पुराने चोट का सही इलाज न होना या शारीरिक गतिविधियों की कमी।

अचानक से वजन कम होना

अगर बिना किसी प्रयास के आपका वजन अचानक से कम हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। वजन कम होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे असंतुलित आहार, तनाव या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। सही समय पर पहचान और इलाज से आप इस समस्या से बच सकती हैं।

खास खबर

सेवा सेतु से आसान हुई शासकीय सेवाओं की राह

रायपुर। शासन की महत्वाकांक्षी पहल सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने में प्रभावी साबित हो रहा है। पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों बच रहे हैं तथा कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। कोरबा जिले की पोड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम सुतर्रा निवासी कुमारी निधि सेन ने सेवा सेतु के माध्यम से समयबद्ध सेवा का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिए ग्राम सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया। पटवारी प्रतिवेदन सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत उनका आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध रूप से निराकृत किया गया और उन्हें मात्र एक सप्ताह के भीतर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। निधि ने बताया कि आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक पूरी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े, जिससे समय और आर्थिक व्यय दोनों की बचत हुई।

मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। इसी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के आरोपों की जांच के बाद जिला प्रशासन ने डी.डी. अस्पताल, सेमरा के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उसके ऑपरेशन थियेटर एवं आईसीयू वार्ड को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन (लाइसेंस) अस्थायी एवं सशर्त रूप से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट तथा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई 22 जून 2026 को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल से सिम्स बिलासपुर रेफर की गई प्रसूता ज्योति सोनवानी के उपचार से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। घटना के पश्चात परिजनों और नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच टीम गठित कर अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण कराया।

‘सुपर अल नीनो’ की चुनौतीः धमतरी में कृषक मित्रों को मिला अल्प वर्षा से निपटने का गुरुमंत्र

वैज्ञानिक खेती, सीधी बुवाई और फसल बीमा से सुरक्षित होगी किसानों की उपज, गांव-गांव फैलेगा जागरूकता का संदेश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जलवायु परिवर्तन और ‘सुपर अल नीनो’ के कारण संभावित अल्प एवं अनियमित वर्षा की चुनौती से निपटने के लिए धमतरी के कृषि विभाग में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स ‘आत्मा’ योजना के तहत आयोजित इस विशेष सत्र में जिलेभर के कृषक मित्रों को आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खेती और फसल बीमा के प्रति जागरूक किया गया, ताकि वे इस ज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचा सकें।

प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने कम वर्षा की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कृषक मित्रों को प्रेरित किया गया कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों को समय रहते जागरूक करें।

वैज्ञानिकों ने विपरीत मौसम की परिस्थितियों से निपटने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, दलहनी (दालें) और तिलहनी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। पानी की बचत के लिए वैज्ञानिक तरीके से ‘डायरेक्ट सीडेड राइस’ तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया। इसी तरह खेतों में उपलब्ध पानी का सही उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय बताए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ, आत्मा के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक सहित आत्मा योजना के जिला व विकासखंड स्तरीय अधिकारी- कर्मचारी और कृषक मित्र उपस्थित थे। प्राकृतिक आपदाओं और सूखे के जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। योजना के जिला प्रबंधक ने धान, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी और रागी जैसी अधिसूचित फसलों की बीमा प्रक्रिया, पात्रता और अंतिम तिथि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कृषक मित्रों से अपील की कि वे अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा सुनिश्चित कराएं ताकि किसी भी नुकसान की भरपाई हो सके।

उत्पादन और आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य

कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों ने कृषक मित्रों का आह्वान किया कि वे इस प्रशिक्षण में सीखी गई आधुनिक कृषि तकनीकों और शासकीय योजनाओं की जानकारी को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रसारित करें। जब किसान वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप खेती करेंगे, तभी विपरीत मौसम में भी जिले का कृषि उत्पादन और किसानों की आय सुरक्षित रह सकेगी।

सहकारिता सप्ताहः सहकार से समृद्धि का संकल्प हुआ सशक्त किसानों को योजनाओं और आधुनिक कृषि की मिली नई दिशा

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुंगेली। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन के सफल पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को कृषि उपज मंडी परिसर, मुंगेली में जिला स्तरीय सहकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सहकारी समितियों के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता कर सहकार से समृद्धि के संकल्प को मजबूत किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास एवं अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, सहकारी योजनाओं तथा शासकीय सुविधाओं की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में सहकारी समितियों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि समितियों की सदस्यता से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से प्राप्त होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में खरीफ सीजन को देखते हुए खाद एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

विधायक मोहले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार है। उन्होंने किसानों से सहकारी समितियों से जुड़कर उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान जिलेभर में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले की सभी सहकारी समितियाँ अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीणों को अनेक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही माइक्रो एटीएम सुविधा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को भी अधिक सुलभ बनाया गया है।

सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सहकारिता विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को लागत कम कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समिति पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान किया गया।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विद्यासागर साहू ने अपनाई स्वच्छ ऊर्जा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला निवासी विद्यासागर साहू ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर रूफ्टॉप सिस्टम स्थापित किया है। इससे वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तथा भविष्य में बिजली खर्च में बचत का लाभ प्राप्त करेंगे। श्री विद्यासागर साहू ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदन कर अपने घर में सोलर रूफ्टॉप सिस्टम स्थापित कराया। योजना का बैंकिंग प्रक्रिया छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक भर्रेगांव शाखा से पूरी हुई। योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन से 30 हजार रूपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई है। सब्सिडी दावा की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है तथा शीघ्र ही राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी।

विद्यासागर साहू ने बताया कि सोलर रूफ्टॉप सिस्टम का स्थापना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में संयंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। मोर बिजली मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन सोलर पैनल द्वारा उत्पादित बिजली एवं बिजली की खपत की जानकारी आसानी से देख रहे हैं। इससे ऊर्जा उत्पादन की निगरानी सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है। विद्यासागर ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सहकारी सप्ताहः कुनकुरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, बड़ी संख्या में नागरिकों ने उठाया लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह के अंतर्गत जशपुर जिले में जनहितकारी गतिविधियों का सिलसिला जारी है।

इसी क्रम में शनिवार को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुनकुरी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी स्थित जनऔषधि केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की अनदेखी नहीं करने तथा समय पर उपचार लेने की सलाह दी।

शिविर के दौरान नागरिकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम एवं योग, स्वच्छता तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई।

सहकारिता के माध्यम से जनकल्याण को मिल रही नई दिशाः कार्यक्रम में सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही। स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक शिविर का लाभ उठाते हुए इसे उपयोगी पहल बताया।

सहकारी सप्ताह के दौरान जिले में किसानों और आम नागरिकों के हित में स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा जनजागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

केरेमुड़ा में किसानों को दी गई ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की वैज्ञानिक खेती की कमान

जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के लिए वरदान बनेगी ग्राफ्टेड सब्जीः धमतरी में वैज्ञानिक प्रशिक्षण संपन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खरीफऔर रबी मौसम में बदलती जलवायु की चुनौतियों के बीच किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कम लागत में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन दिलाने के लिए धमतरी जिले में एक बड़ी पहल की गई है। जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम केरेमुड़ा में ग्राफ्टेड (कलमी) टमाटर और बैंगन की वैज्ञानिक खेती पर एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण का संचालन प्रदान संस्था द्वारा किया गया।

इस प्रशिक्षण में नगरी और मगरलोड विकासखंड की कृषि सखियों, मास्टर ट्रेनर्स सहित बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को ग्राफ्टेड सब्जी उत्पादन की आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों से रूबरू कराकर उन्हें जलवायु-अनुकूल, टिकाऊ और अधिक मुनाफे वाली खेती के लिए प्रेरित करना था।

अधिकारियों ने बताया कि इस आजीविका मिशन के तहत नगरी विकासखंड में किसानों को कुल 1 लाख 1 हजार 800 ग्राफ्टेड पौधों का वितरण किया गया है। इसमें 51 हजार 800 ग्राफ्टेड टमाटर और 50 हजार ग्राफ्टेड बैंगन के पौधे शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ग्राफ्टेड पौधे सामान्य पौधों की तुलना में बेहद मजबूत होते हैं। इनकी जड़ प्रणाली सशक्त होती है, जिससे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये पौधे विपरीत मौसम में भी तेजी से बढ़ते हैं और बंपर पैदावार देते हैं, जिससे किसानों को बाजार में अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलती है।

ग्राफ्टिंग एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें एक पौधे के मजबूत जड़ वाले हिस्से (रूटस्टॉक) पर दूसरे अधिक उत्पादन देने वाले पौधे के ऊपरी हिस्से (सायन) को जोड़कर एक नया ‘सुपर प्लांट’ तैयार किया जाता है। इससे बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार दोगुनी तक हो जाती है। प्रशिक्षण की सबसे खास बात रहा खेत पर आयोजित ‘लाइव फील्ड डेमोंस्ट्रेशन’ (व्यावहारिक प्रदर्शन)। इसमें किसानों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर सीधे खेत में ले जाकर भूमि की तैयारी, पौधों का उपचार, वैज्ञानिक तरीके से रोपण मल्चिंग, नमी संरक्षण और जैविक कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन करके दिखाया गया। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों ने समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन मृदा स्वास्थ्य , जैव उर्वरकों का सही उपयोग और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन की बारीकियां सिखाईं। संवाद सत्र में किसानों ने खेती के दौरान होने वाली अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को रखा, जिसका विशेषज्ञों ने मौके पर ही वैज्ञानिक समाधान बताया। इस पूरी मुहिम को धरातल पर उतारने में ‘गट्टासिल्ली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी’ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके माध्यम से किसानों को उन्नत ग्राफ्टेड पौधे और जरूरी जैविक खाद-सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं प्रदान संस्था द्वारा कृषि सखियों और किसानों को पूरे फसल चक्र के दौरान लगातार तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जा रहा है।

जिला पंचायत धमतरी के मार्गदर्शन में चल रही यह त्रिकोणीय पहल (प्रशासन, स्वक्ष्क और प्रदान संस्था) नगरी और मगरलोड विकासखंड में आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ खेती का एक नया मॉडल पेश कर रही है। इससे न केवल ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर पोषण सुरक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा।

125 दिनों के रोजगार से बढ़ी उम्मीदें

रायपुर। ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर जीवन का आधार देने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ने गांवों में नई उम्मीद जगाई है। रोजगार की अवधि बढ़ाकर 125 दिन किए जाने और मजदूरी दर में वृद्धि से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। मुंगेली जिले के ग्राम लिम्हा की निवासी गोमती साहू ने इस योजना को ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण परिवारों को वर्ष में केवल 100 दिनों का रोजगार मिलता था, जिससे कई बार आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता था।

खास खबर

बिलासपुर में पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर खुद लगाई फांसी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिवार को पति ने पहले कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के समय दंपती के दो मासूम बच्चे घर के एक कमरे में बंद मिले। पुलिस को किराए के मकान से पति-पत्नी की लाश बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या के बाद आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अशोक देवांगन (52) और उनकी पत्नी धनेश्वरी देवांगन (49) के रूप में हुई है। शनिवार सुबह घर के अंदर कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और मकान मालिक मौके पर पहुंचे। परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। एक कमरे में अशोक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि धनेश्वरी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। तोरवा थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और परिजनों व आसपास के लोगों के बयान के आधार पर ही घटना की वास्तविक वजह साफ हो सकेगी।

रास्ता देने की बात पर 5 युवकों ने मिलकर की मारपीट

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में एक मारपीट की घटना घटित हुई है। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जहां रास्ता देने की बात पर दो युवकों ने कार के सामने बाइक को अढ़ा दिया और बहस होने पर अपने 3 दोस्तों को बुलाकर कार चालक की हाथ-मुक्को व डंडे से पिटाई कर दी। कोतरा रोड सावित्री नगर का रहने वाला मयंक यादव अपनी कार पर सवार होकर काम पर जा रहा था। तभी उसके घर के पास ही मोड़ पर सुरजीत सिंह बघेल और रोशन महंत उसके बाइक के सामने कार को खड़ी कर दिए। सुरजीत सिंही व रोशन महंत ने अपने 3 अन्य दोस्तों को मोबाइल पर कॉल कर बुला लिया। पांचो युवकों ने मिलकर मयंक की हाथ-मुक्को व डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन सौंपकर मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवक ने थाना में मारपीट की लिखित शिकायत की थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। जिसके बाद मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नर चीतल के अवैध शिकार का खुलासा, सात आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार वन, वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा अवैध शिकार के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में कवर्धा परियोजना मंडल ने नर चीतल के अवैध शिकार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।

सरकार की सख्ती से वन्यजीव अपराधों पर लग रहा अंकुश

वन विकास निगम के बोड़ला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट स्थित जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाकर लगभग तीन वर्ष के नर चीतल का शिकार किया। इसके बाद उसके मांस को पकाकर आपस में बांटने की तैयारी की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर वन विकास निगम की टीम ने तत्काल योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर दबिश दी और सभी सात आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से लगभग 500 ग्राम पका हुआ चीतल का मांस, नायलॉन की रस्सी, तीन कुल्हाड़ियां, स्टील के तार एवं लकड़ी से बने फंदे तथा खून से सना थैला बरामद कर जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

सघन निगरानी और गश्त से मिल रही सफलता

वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, सूचना तंत्र को मजबूत करने तथा विशेष निगरानी अभियान चलाने के कारण वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अवैध शिकार करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार की स्पष्ट नीति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग आधुनिक निगरानी व्यवस्था, नियमित गश्त और प्रभावी सूचना तंत्र के माध्यम से वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहा है। वन्यजीवों का अवैध शिकार करने या प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री कश्यप ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वन्यजीवों के संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। अवैध शिकार या वन अपराध की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर प्रदेश की समृद्ध वन्यजीव संपदा और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पुरानी रंजिश में पिता पर हमला, 6 आरोपी अरेस्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बेटी से बात करने से मना करने पर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने देर रात पीड़ित के घर में घुसकर लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले में शामिल सभी 6 आरोपियों को भिलाई से गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पिनकापार चौकी क्षेत्र के ग्राम संबलपुर का है। घटना 30 जून की देर रात की है। ग्राम संबलपुर निवासी गौकरण साहू परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी 6 आरोपी दो बाइक और एक स्कूटी से गांव पहुंचे। इनमें से दो आरोपी बाहर

निगरानी करते रहे, जबकि चार आरोपी घर के अंदर घुस गए।

आरोपियों ने बांस के डंडे और लकड़ी के राफ्टर से गौकरण साहू के सिर, पीठ और कमर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर उनकी 13 साल की बेटी जाग गई, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले गौकरण साहू ने मुख्य आरोपी भानूप्रताप जैन को अपनी नाबालिग बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उन्होंने भानूप्रताप और उसके माता-पिता को घर बुलाकर फटकार भी लगाई थी। इसी बात से नाराज होकर भानूप्रताप ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की साजिश रची और हमला कराया।

देवरी थाना प्रभारी मनीष शेंडे ने बताया कि घायल गौकरण साहू का इलाज जारी है। उनके सिर पर गहरे चोट के निशान हैं। उनकी पत्नी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109, 332(2) और 191(3) के तहत मामला दर्ज किया गया।

हथियार और वाहन जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाठी-डंडे, लकड़ी का राफ्टर, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

रायपुर में नशीली गोलियां बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोलबाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली नाइट्रोसन-10 टैबलेट के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से 300 प्रतिबंधित नाइट्रोसन-10 टैबलेट, दो मोबाइल और नकदी समेत करीब 1.50 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। जिनकी पहचान कबीर नगर निवासी मोहम्मद असफाक (25), आजाद चौक निवासी शिवम ढीमर (22) और धमतरी जिले के कुरूद निवासी तुषार ढीमर (20) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि दाई कोरा भवन के सामने कुछ युवक

प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गोलबाजार थाना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई की।

पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की तो संदिग्ध युवक भागने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके बैग से 300 प्रतिबंधित नाइट्रोसन-10 टेबलेट बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गोलबाजार थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस नशीली दवाओं की सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, मामले में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

जांजगीर-चांपा में दो सड़क हादसे, एक की मौत

कार-बाइक भिड़ंत में 3 घायल, कैप्सूल वाहन ने अधेड़ को कुचला

श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटनाएं बिर्रा और बम्हनीडीह थाना क्षेत्रों में हुई।

पहली घटना बिर्रा थाना क्षेत्र के टॉकीज के पास हुई। यहां वार्ड नंबर 9 निवासी छत्तु पटेल पैदल चल रहे थे, तभी शिवरीनारायण की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वाहन के पहिए के नीचे आने से छत्तु पटेल का कमर से नीचे का हिस्सा बुरी तरह कुचल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बिर्रा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया।

दूसरी घटना बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम

पिपरदा की मुख्य सड़क पर हुई। यहां एक कार और बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

इस हादसे में कार चालक को भी हल्की चोटें आईं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बम्हनीडीह पुलिस मामले की आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है।

धमतरी में राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध रेत परिवहन करते 8 ट्रैक्टर जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के कड़े निर्देशानुसार आज राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टरों को रंगे हाथों जब्त किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन को लगातार कोलियारी-धमतरी मार्ग पर अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए राजस्व और

खनिज विभाग की एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने जब मार्ग पर घेराबंदी कर रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को रोका और उनसे खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज (रॉयल्टी पर्ची/अनुमति) की मांग की, तो वाहन चालक कोई भी संतोषजनक कागजात पेश नहीं कर सके। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 8 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। इन सभी वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया है और खनिज अधिनियम के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन की चेतावनी: आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद रेत और अन्य खनिज माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान आगे भी इसी तरह बिना रुके जारी रहेगा और पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और केवल वैध अनुमति के साथ ही खनिजों का परिवहन करें।

उर्वरकों की कालाबाजारी पर राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस, बेमेतरा में 275 बोरी यूरिया जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

बेमेतरा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को समय पर, उचित मूल्य पर और गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित 275 बोरी यूरिया जब्त कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज डडसेना के मार्गदर्शन में गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा जिलेभर में लगातार औचक निरीक्षण और छापामार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त

मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर अनुचित लाभ कमाने के प्रयासों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

इसी अभियान के तहत प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर उड़नदस्ता दल ने ग्राम जानो, तहसील देवकर में अँजोर वर्मा के परिसर में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 275 बोरी यूरिया का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर संपूर्ण उर्वरक को विधिवत जब्त कर लिया गया तथा संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्राप्त जवाब के परीक्षण के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने जब्त किए गए उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को केवल मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक ही उपलब्ध कराए जाएं और किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा निम्न गुणवत्ता की सामग्री बाजार में न पहुंचे।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। यदि कोई निजी कृषि केंद्र, उर्वरक विक्रेता अथवा सहकारी संस्था इस प्रकार की अनियमितता करते हुए पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाएगा।

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन पूरे जिले में लगातार निगरानी कर रहा है और शिकायत प्राप्त होते ही बिना पूर्व सूचना के तत्काल जांच एवं छापामार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा, कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता तथा कृषि आदानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में चल रही इस तरह की सतत कार्रवाई न केवल कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने में सहायक होगी, बल्कि किसानों का विश्वास भी मजबूत करेगी कि सरकार उनकी मेहनत, उनकी फसल और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अधिक मूल्य पर बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो तत्काल कृषि विभाग अथवा जिला प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर में कारोबारी से 14.37 लाख की धोखाधड़ी

रायपुर। रायपुर के कबीर नगर स्थित एक ऑटो पार्ट्स कारोबारी से 14.37 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि, दुकान के तीन कर्मचारियों ने ग्राहकों को सामान बेचने के बाद बिक्री की रकम दुकान में जमा नहीं की और अपने पास रख ली। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दुकान के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड, बिल, कैश के हिसाब और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि, बिक्री के मुकाबले दुकान में रकम जमा नहीं हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

जमीन दिलाने नाम पर 7.55 लाख ठगे

रायपुर। कोरबा जिले के करतला निवासी भुवनदास मानिकपुरी ने रायपुर के खम्हारडीह निवासी अमितेश सतपथी पर जमीन दिलाने और बाद में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 7.55 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायकर्ता ने बताया कि, अक्टूबर 2024 में दोस्त अनिल साहू के माध्यम से अमितेश सतपथी से संपर्क हुआ था। आरोपी ने जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया और अलग-अलग तारीखों में फोन-पे, एनईएफटी और बैंक ट्रांसफर के जरिए शिकायतकर्ता, उसके पिता और दोस्तों से कुल 7 लाख 55 हजार रुपए ले लिए। काफी इंतजार के बाद भी जमीन नहीं दिलाई गई।

- डिजिटल गवर्नेंस, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि और नेतृत्व विकास पर मंथन
- पिछले चिंतन शिविरों के परिणाम स्वरूप ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे नवाचार हुए साकार

चिंतन शिविर 3.0 से सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार होगी : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। चिंतन शिविर 3.0 का उद्देश्य शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति-निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि शासन की कार्यसंस्कृति में निरंतर सुधार और नवाचार का माध्यम बन चुका है। पिछले दो संस्करणों से प्राप्त सुझावों को सरकार ने प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसरोकारों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना ही इस शिविर का मूल उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर 3.0 के प्रथम दिवस में नेतृत्व विकास, सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा कृषि समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक गौर गोपाल दास ने नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन, सेवा-भाव और जनप्रतिनिधियों के नैतिक दायित्वों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मूल्य-आधारित नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासन को प्रभावी सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।

शिविर में नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विषय पर संबोधित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5जी, ड्रोन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तथा डेटा-आधारित प्रशासन के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीक आधारित सेवा वितरण, नवाचार, रोजगार सृजन तथा डिजिटल समावेशन के लिए छत्तीसगढ़ के समक्ष उपलब्ध अवसरों की भी चर्चा की।

कृषि विषयक सत्र कृषि से समृद्धि में कृषि अर्थशास्त्री डॉ. रमेश चंद तथा कृषि विशेषज्ञ टी. विजय कुमार ने प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क और तकनीक आधारित कृषि सुधारों पर अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने देश के विभिन्न राज्यों के सफल मॉडलों की जानकारी देते हुए किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने समूह आधारित विचार-मंथन में भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई, जिससे फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु जैसे महत्वपूर्ण नवाचार भी इसी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम हैं। आज सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 520 से अधिक सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आमजन को सरल, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर 3.0 से प्राप्त सुझाव सुशासन, तकनीक आधारित प्रशासन, कृषि सुधार, विभागीय समन्वय और जनसेवा के नए मानक स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार नवाचार, ज्ञान, तकनीक और प्रभावी नीति-निर्माण को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी तथा चिंतन शिविर से निकले विचारों को शीघ्र ही ठोस नीतिगत और प्रशासनिक पहलों के रूप में लागू किया जाएगा।

स्कूली बच्चों के रेडीमेड गणवेश की गुणवत्ता उच्च स्तरीय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा गोदाम स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से रेडीमेड गणवेश का शत-प्रतिशत कड़ा गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। इसके उपरांत ही स्कूलों में गणवेश की आपूर्ति की जाती है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले, विकासखंड या स्कूल/संकुल से ऐसी शिकायत नहीं है कि गणवेश गुणवत्ता विहीन है द्य छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा

गणवेश की ?गुणवत्ता की शत-प्रतिशत जांच के बाद ही स्कूलों को आपूर्ति की जाती है।

लोक शिक्षण संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के किसी भी जिले या स्कूल से गणवेश की गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग के द्वारा संघ के गोदाम प्रभारियों और तकनीकी टीम के प्रतिवेदन में भी गणवेश की गुणवत्ता को पूरी तरह मानक के अनुरूप पाया गया है।

शासन की मंशानुरूप कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए यह रेडीमेड गणवेश राज्य के स्थानीय बुनकरों से तैयार कराए जा रहे हैं और महिला स्व- सहायता समूहों के माध्यम से इनकी सिलाई कराई जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में प्रति छात्र 2-2 सेट गणवेश तथा रायपुर एवं दुर्ग संभाग के जिलों में आंशिक रूप से गणवेश की आपूर्ति की जा चुकी है और वर्तमान में गणवेश की आपूर्ति का यह कार्य प्रगति पर है।

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रतिवर्ष लोक शिक्षण संचालनालय की मांग के अनुसार पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ गणवेश की आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद यदि भविष्य में किसी भी जिले या संकुल से गणवेश की गुणवत्ता या साइज को लेकर कोई व्यावहारिक समस्या सामने आती है, तो संघ द्वारा तत्काल तकनीकी परीक्षण कराकर गणवेश को बदलने (रिप्लेस करने) की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों और पालकों से अपील है कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक और अपूर्ण खबरों पर ध्यान न दें। राज्य शासन बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।?

ढैंचा की हरी खाद से जैविक खेती की ओर बढ़े किसान हिमांशु बंजारे

महासमुंद। जिले के विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम बड़ेसाजापाली के प्रगतिशील किसान हिमांशु बंजारे ने जैविक खेती को अपनाकर टिकाऊ कृषि की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने अपने 0.80 हेक्टेयर कृषि रकबे में ढैंचा की हरी खाद की फसल बोई है, जो वर्तमान में लगभग 30 दिन की हो चुकी है। हिमांशु बंजारे ने बताया कि ढैंचा की फसल को खेत में पलटकर हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा।

इससे भूमि की उर्वराशक्ति में सुधार होगा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी तथा आगामी फसल की उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है। उनका कहना है कि जैविक खेती अपनाने से खेती की लागत कम होने के साथ-साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण और विभागीय अभिसरण पर दिया जोर

बस्तर में कृषि विकास को मिलेगी गतिः कृषि मंत्री नेताम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को बीजापुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों के कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए करें प्रेरित

कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों को लेकर किसानों में किसी प्रकार का भ्रम या भय उत्पन्न न किया जाए। किसानों को वैज्ञानिक सलाह, उन्नत तकनीकों तथा फसल प्रबंधन के माध्यम से बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने उपलब्ध भू-जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए नलकूप, कुएं एवं अन्य सिंचाई साधनों का विस्तार कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने धान के साथ-साथ मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, श्रीअन्न तथा अन्य वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। दंतेवाड़ा जिले में मक्का उत्पादन के सफल मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के निर्देश दिए।

'मिलेट्स, जैविक खेती और बीज उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा'

श्री नेताम ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में उत्पादित श्रीअन्न (मिलेट्स) के बेहतर विपणन की व्यवस्था विकसित की जाए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।

उन्होंने दलहन एवं तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देने, बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा रबी फसलों के रकबे में वृद्धि हेतु सौर सिंचाई पंपों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया।

पशुपालन और मत्स्य पालन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

कृषि मंत्री ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए मोबाइल वेटरनरी यूनिट एवं टोल फ्री नंबर 1962 का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य विभागों के समन्वय से एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मत्स्य एवं उद्यानिकी क्षेत्र के विकास पर विशेष फोकस

बैठक में मत्स्य पालन विभाग को एकीकृत मत्स्य पालन मॉडल विकसित करने, किसान क्रेडिट कार्ड एवं तालाब पट्टा वितरण के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने तथा शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा प्रक्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण करने पर भी बल दिया गया।

उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने बीजापुर जिले में हल्दी, नारियल एवं अन्य व्यावसायिक फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए कार्ययोजना तैयार करने, ऑयल पाम योजना का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय शासकीय भूमि पर प्रदर्शन प्लॉट विकसित कर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि राहुल देव सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वीबी-जीरामजी योजना से दिव्यांगजनों को मिला सम्मान और रोजगार

125 दिनों का रोजगार, 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और मेट की जिम्मेदारी से बढ़ा आत्मविश्वास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासन की विकसित भारत-जीरामजी (ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन) योजना दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना से उन्हें अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य मिल रहा है। पहले जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब वीबी-जीरामजी योजना के अंतर्गत 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। इससे दिव्यांग हितग्राहियों की आय बढ़ी है और उनका आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुंदरा निवासी दिव्यांग चंद्रप्रकाश साहू को वीबी-जीरामजी योजना के तहत 100 मजदूरों के लिए मेट की जिम्मेदारी दी गई है। वे बताते हैं कि पहले उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, लेकिन अब 125 दिनों तक काम और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

उन्होंने कहा कि मेट की जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गर्व की बात है। इससे उन्हें समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

सम्मान ने बढ़ाया हौसला

चंद्रप्रकाश साहू को राजनांदगांव प्रवास के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वे बताते हैं कि यह सम्मान उनके जीवन का अविस्मरणीय पल है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आगे बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम कोहका की दिव्यांग सुश्री रंभा मंडावी को भी वीबी-जीरामजी योजना के तहत मेट का कार्य मिला है। पहले उन्हें मनरेगा में 261 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के साथ 100 दिनों का रोजगार मिलता था। अब उन्हें 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे उनकी आय बढ़ी है और परिवार को आर्थिक संबल मिला है। सुश्री रंभा मंडावी ने बताया कि वे मेट के रूप में कार्य करने के साथ-साथ गांव के लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देती हैं, ताकि पात्र हितग्राही समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्हें भी जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान से उनका उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं।

दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद बनी योजना

दोनों हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वीबी-जीरामजी योजना दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक आजीविका का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के तहत बढ़े कार्य दिवस, बेहतर मजदूरी और जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व ने उनके जीवन में नई उम्मीद, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा का संचार किया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950